which has now come down to 12.20 lakh tonnes only, annually. because of the negligence of MMTC and less number of ships calling at Paradip to export ore. The Central Government should take immediate steps to clear this backlog of 3.1 million tonnes at the Port and should ensure regular export of 40 lakh tonnes of iron-ore annually, so that thousands of Adivasi workers who earn their livelihood by working in the mines get regular work and the economy of the State is not shattered.

(v) NEED TO PROVIDE ADEQUATE FACILITIES TO WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY BY THE BANKS.

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य भागों में बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इन बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, जन जातियों, स्वतंत्रता सेनानियों या अन्य कमजोर वर्गों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, आई० आर० डी०, एस० एफ० डी० ए०, एन० आर० ई० पी० या अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उस से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उन गरीबों को दी जा रही सुविधाओं में लगातार बाधक बन रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव में मेरे ही गृह विकास खंड गगहा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की यह दशा है कि सारी अर्हताओं को पूरा करने के बाद भी लगभग 6 माह तक उन गरीबों को उस बैंक की तरफ किराया-भाड़ा लगा कर दौड़ना पड़ता है। यही हालत प्रत्येक विकास खंडों खंडों की है। इसके बाद कहीं जाकर उन गरीबों को ऋण या अनुदान प्राप्त हो पाता है। जबकि ये सभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और उनकी नीति है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में हरिजनों, गिरिजनों तथा कमजोर वर्गों की दशा को सुधारने के लिए काम करेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप हमारी सरकार की जो समाजवादी एंव प्रगतिशील नीति है उसे सही ढंग से उन ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंचाया जा रहा है।

अत: वित्त मंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि वे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहें कि वे बैंक हमारी प्रगतिशील नीति को सफल बनाने के लिए कम से कम समय में उन गरीबों को ऋण या अनुदान की रकम दें।

(vi) RECONSIDERATION BY GOVERNMENT OF THE PROPOSED TOUR OF INDIAN CRICKET TEAM TO BRITAIN.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): The recent decision by some of Britain's leading cricketeers to offer their services to South Africa in exchange for substantial payment raises the question whether the Indian cricket team should go ahead with their proposed our of Britain this summer or call it off. The issue cannot be evaded by the Board of Control. Many professionals who do not deserve to be called sportsmen have been regularly coaching South African players and taking part in league matches. To such people, money is more important than holding alloft the banner of human right or UN resolutions on the subject. The news about the tour of British criketeers to South Africa has been accompanied by another item about a Register drawn up by the UN's Special Committee against Apartheid which reveals that more than 360 sportsmen from 29 countries have taken part in

[Shri Eduards Faleiro]

exchange with South Africa between April and December, 1981, and out of this number, more than 100 countries are from Britain and over '80 from the United States, which have been described in that Register as the main collaborators of apartheid.' India can have no deal with any country that ignores the suppression of basic human rights. Much less so in the case of South Africa where people of Indian descent still suffer may indignities.

I, therefore, urge the Government of India and the sports organisations in this country to black-list all those involved in collaboration exchanges with South Africa and to reconsider its decision to send a cricket team to Britain in case any of the players now touring South Africa is to play in the British team.

(vii) APPOINTMENT OF A PROBE COMMITTEE TO LOOK INTO THE WORKING OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, PARTICULARLY THE CARDIOLIGY DEPARTMENT.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस) नई दिल्ली के हृदय शल्य विभाग को जितना ही देश में अच्छा नाम था, उतना ही वह विभाग बदनाम हो रहा है। गरीब एंव गंभीर दिल के रोगी की मृत्यु बेमौत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार उस संस्थान के वरिष्ठ सर्जन हैं। एक सर्जन, जो प्रोफेसर और हृदय शल्य विभाग के प्रधान भी हैं, को आंख की बीमारी है, जिन्हें कम दिखाई पड़ता है। फिर भी सरकार द्वारा उनके सेवा-अवधि में वृद्धि की गई है। उसी विभाग के एक दूसरे प्रोफेसर और सर्जन को मिरगी की बीमारी है। कई बार आपरेशन के समय ही वे मूर्च्छित हो चुके हैं। इस विभाग के बड़े डाक्टर चुने हुए मरीजों को ही कार्यालय में बुलाकर देखते हैं। आम रोगी के साथ इनका व्यवहार क्रूर होता है। अच्छे डाक्टर के प्रमाण पत्र पाने के लोभ में वैसे ही चुने हुए मरीजों का आपरेशन किया जाता है, जो आसान किस्म के हैं।

गरीब और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को या तो डांट-डपटकर भगा दिया जाता है या आपरेशन की तिथि इतनी लम्बी दी जाती है कि उसी अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से गंभीर एंव गरीब मरीजों से आपरेशन हेतु हजारों रुपए जमा करा लिए जाते हैं, उनसे काफी मात्रा में खून भी ले लिया जाता है, आपरेशन की तिथि भी निश्चित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपरेशन नहीं किया जाता। फलस्वरूप बहुत से रोगियों की मृत्यु आपरेशन के पहले ही हो जाती है।

अभी कुछ ही समय पहले ग्राम मोकामा के श्री नाथी पासवान, पिता श्री राम खिलावन पासवान, जिला पटना (बिहार) मेरे पास आया था। वह हृदय रोग का रोगी था। मैंने उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भेज दिया। वह एक 25 साल का गरीब हरिजन नौजवान था। उस से 18 हजार रुपये आपरेशन हेतु जमा करवा लिए गए। कई बार उस के आपरेशन की तिथि निश्चित की गई। उस से पर्याप्त मात्रा में खून भी ले लिया गया। पुन: 15